

शिक्षा का अर्थशास्त्र (Economic of Education)

Policy Economic and Planning:

शिक्षा के अर्थशास्त्र से अर्थशास्त्र से सम्बंधित आर्थिक विषयों (मुद्दों) के से हैं। शिक्षा से जुड़े आर्थिक मुद्दे हैं- शिक्षा की मांग, शिक्षा के लिए निश्चित वित्त की व्यवस्था, विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों और नीतियों की प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन आदि।

Economic — Education

⇒ Concept of Economic of Education → शिक्षा के अर्थशास्त्र की अवधारणा

* ऐसा विषय जिसमें ~~को~~ ~~प्रधान~~ से सम्बंधित अध्ययन करते हैं उसे अर्थशास्त्र (पैसा) कहते हैं। SSA

* निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सरकार → Investment MDM NVS

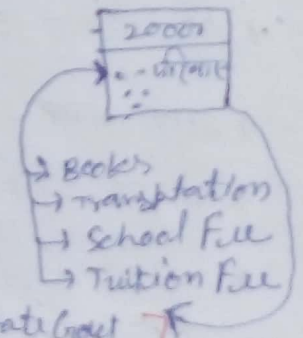
* Demand & Supply

① * Vocational Education
↓
B.Ed., D.El.Ed., Higher Education

② * Professional Education

③ वित्त की व्यवस्था (Financing) → (Govt) [State Govt, Central Govt] → Public Funding

④ Education Production Functions → Engineer, Doctor, Teacher



निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा →

- * संविधान के 21 A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया है। (86वें संशोधन)
- * 6-14 वर्ष तक के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक अपने घर के पास स्थित स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आधिकार है।
- * सरकारी मदद पाने वाले निजी स्कूलों को बसजोर वर्गों और पिछड़े तबके के 25% बच्चों को प्रवेश देना होगा।
- * सरकार बच्चों को मूनीकार्म, पाठ्य-पुस्तकें, मध्यम भोजन तथा निःशुल्क स्कूलिंग उपलब्ध करायेंगी।

मध्यम भोजन योजना (Mid Day Meal) →

- * यह योजना 15 Aug 1995 में केंद्र सरकार द्वारा लाई गयी।
- * इसका संचालन State Govt and central Govt
- * कक्षा -1 से 8 तक (1-5 लक पहले)
- * बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना ताकि उनके शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाना।
- * प्राथमिक कक्षाओं में दारों के विद्यालय में स्कूलों की प्रवृत्ति को विकसित करना तथा Drop out को रोकना।
- * In Rationment को बढ़ाना
- * मीनू अलग-2 होना चाहिए।
- * भारतीय खाद्य विभाग द्वारा गेहूँ तथा चावल उपलब्ध करायी जाती थी।

नवीन विद्यालय - JNV

- * रहने की सुविधा
- * खाने की सुविधा
- * मुफ्त पुस्तकें दी जाती हैं
- * पाठ्य लक्ष्य क्रियाएँ. Co-curricular Activity
- *

1-5-

* शिक्षा का आर्थिक विकास (Economic of Education Development) →

किसी भी देश के आर्थिक विकास से तात्पर्य सामान्यतः उसकी आय की उत्तरोत्तर वृद्धि से लिया जाता है और राष्ट्रीय आय सामान्यतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) से मापी जाती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रशीत आदि की घिसावट घटाने से विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय मानते हैं। परन्तु आर्थिक विकास के लिए तो आर्थिक विकास किया नहीं जाता; उससे व्यक्तियों के जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि होनी चाहिए। जीवन स्तर उठाने से तात्पर्य केवल शैरी, कपड़ा और मकान की पूर्ति से नहीं होता और नही इसके बाद उच्च स्तर के भोजन, रूपड़े और मकान की पूर्ति आदि अन्य संसाधनों के उपलब्ध होने से होता है अपितु इस सबके साथ-2 उपयुक्त शिक्षा, एवं स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होने, उपयुक्त सुरक्षा सेवा उपलब्ध होने और उपयुक्त यातायात साधन आदि उपलब्ध होने से होती है। इसमें वह सब समाहित होता है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी एवं लाभकर है।

राष्ट्रीय आय बढ़ने के बाद भी राष्ट्र के नागरिकों का जीवन स्तर ऊँचा न उठे अपितु उसमें गिरावट आये। जब राष्ट्र की जनसंख्या में वृद्धि की दर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर से अधिक होती है। इसलिए अब राष्ट्र के आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय के स्थान पर राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय के रूप में मापा जाता है। राष्ट्रीय आय को राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के बाद भी राष्ट्र के नागरिकों का जीवन स्तर ऊँचा न उठे। ऐसा तब होता है जब मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। अतः यह भी आवश्यक है कि प्रति व्यक्ति आय के साथ-2 मुद्रा के तात्कालिक मूल्य को भी ध्यान में रखा जाय।

परिभाषा → "किसी देश के आर्थिक विकास से तात्पर्य उस देश की प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर होने वाली वृद्धि एवं परिणामस्वरूप उल्लेख नागरिकों के जीवन स्तर के ऊँचा उठाने उठने से होता है।"